GLOBALCULTURZ Vol.III No.2 May-August 2022 ISSN:2582-6808
Article ID-2022-3-2-004 **Pages:** 533-537 **Language:** Hindi
Date of Receipt: 2022.07.06 **Date of Review:** 2022.07.21 **Date of Pub:** 2022.07.25
Domain of Study: *Humanities & Social Sciences* **Sub-Domain:** *Social Studies*

भारत में जेल सुधारों की ऐतिहासिक समीक्षा

डॉ0 रेखा ओझा

सहायक प्रोफेसर
दर्शन एवं तुलनात्मक धर्म विभाग, विश्वभारती, प० बंगाल, भारत
[Dept. of Philosophy & Comparative Religion
Visva Bharati University
Santiniketan, W. Bengal, India]
E-mail:*drrekha3@gmail.com*

About the Author

Dr. Rekha Ojha is an internationally recognized academic leader in Feminist Philosophy, Ethics, Gender Studies, Film Studies, Spiritual Philosophy and Social Philosophy. She is an Assistant Professor of Philosophy in the Department of Philosophy and Comparative Religion, Visva-Bharati University (A Central University and an Institute of National Importance), Santiniketan. She holds a Ph. D from the North Eastern Hill University, Shillong and an M.A and B.A from the same University. Dr. Rekha has fifteen years of experience in both academia and industry. She is currently working as a Principal Investigator on a Major Project "Alternative to Imprisonment in India: An Ethical Perspective", funded by Indian Council of Philosophical Research, New Delhi. She has authored many books and her articles have appeared in several national and international academic journals. The name of her five important books is:

1. *Women's Right in India: A Feminist Perspective*
2. *The Concept of Equality in human and Gender Right Discourse*
3. *Dalit Women in India*
4. *Intersex Identity: An Ethical Perspective*
5. *Women and Child Trafficking in India*

She has also presented papers in more than 50 National and International Seminars.

Note in English

The prison system as it operates today is legacy of the British rule in our country. It was the creation of the colonial rulers over our penal system with the motive of making imprisonment a terror to wrong doers. It is true to said that a man is not a criminal by birth but the social and economic conditions make him criminal.

This paper is an attempt to highlight some of the issues related to prisoners inside the jail. Prisoners should not be treated inhuman because the main motive of imprisonment is not to punish but to reform a criminal due to which he will be able to live in society normally after the completion of his punishment. The punishment system in Indian is also based on the reformative theory. There were many reforms in the Prison system in India but still there is need of some other reforms because the condition of prisoners in prison is degradable.

शोध सार

बड़े पैमाने पर, हमारे समाज में जेलों का अस्तित्व वैदिक काल से ही एक प्राचीन घटना है, जहाँ शासकों द्वारा अपराध के खिलाफ समाज की रक्षा के लिए असामाजिक तत्वों को एक जगह पर रखा गया था। जेलों को एक ' बंदी का घर '[3] के रूप में माना जाता था जहाँ कैदियों को प्रतिशोधी और निवारक दंड के लिए रखा जाता था। सत्रहवीं शताब्दी के अंग्रेजी राजनीतिक सिद्धांतकार जॉन लॉक ने कहा कि पुरुष मूल रूप से अच्छे थे, लेकिन 'समाज में कुछ हताश पुरुषों' को बनाए रखने के लिए कानूनों की जरूरत थी। अपने आपराधिक कानून में व्यक्त समाज का उद्देश्य व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपने स्वयं के अस्तित्व की रक्षा करना है और सभी नागरिकों के लिए एक अच्छा जीवन जीने के लिए, दूसरों के साथ छेड़छाड़ से मुक्त करना संभव बनाना है।कानून लागू करने वाली संस्था को समाज द्वारा अपने नागरिकों की स्वतंत्रता का पर्दाफाश करने के लिए उन्हें उनके कर्तव्यनिष्ठ आचरण के संबंध में हिरासत में लेने की शक्तियां दी गई हैं।

बीजशब्द-जेल व्यवस्था, भारत, ब्रिटिश शासन, समाज सुधार

शोध आलेख

दो आंखें बारह हाथ एक वी शांताराम द्वारा निर्देशित 1957 की हिंदी फिल्म है, जिसने फिल्म में अभिनय भी किया। इसे हिंदी सिनेमा के क्लासिक्स में से एक माना जाता है और यह मानवतावादी मनोविज्ञान पर आधारित है। फिल्म "ओपन जेल" प्रयोग की कहानी से प्रेरित थी: सतारा के साथ औंध की रियासत में स्वतंत्रपुर, अब, स्वतंत्रपुर महाराष्ट्र के सांगली जिले में अटपदी तहसील का हिस्सा है। इसे पटकथा लेखक जीडी मडगुलकर ने दी। "दो आंखें बारा हाथ"[1] एक आदर्शवादी जेलर आदिनाथ (शांताराम) की कहानी है, जो खूंखार कैदियों को जेल की परिधि में नहीं बल्कि वास्तविक दुनिया में सामाजिक रूप से उत्पादक प्राणियों में सुधार करना चाहता है। उनका आदर्शवाद यूटोपियन नहीं है। जी हां, हम बात कर रहे हैं चौथे, राजाराम वानकुंदरे शांताराम की जेल सुधारों की। उनका यह संदेश कि हर कोई दूसरे अवसर का हकदार है, उसने घंटी बजा दी, क्योंकि उस समय नौकरशाही औपनिवेशिक व्यवस्था का अनुसरण कर रही थी। "ऐ मालिक तेरे बंदे हम" जल्द ही न केवल जेलों में बल्कि देश भर के स्कूलों में एक मुख्य विशेषता बन गया।

एक वास्तविक कहानी से प्रेरित, "दो आंखें बारा हाथ" एक आदर्शवादी जेलर आदिनाथ (शांताराम) की कहानी है, जो खूंखार कैदियों को जेल की परिधि में नहीं बल्कि वास्तविक दुनिया में सामाजिक रूप से उत्पादक प्राणियों में सुधार करना चाहता है। उनका आदर्शवाद यूटोपियन नहीं है। वह एक कैदी के साथ हाथापाई करना चाहता है जो उसे मारना चाहता है, लेकिन एक घंटी के लिए पहुंचता है न कि अपने हमलावर को मारने के लिए एक छड़ी के रूप में। नेक प्रयोग के हिस्से के रूप में, वह छह कैदियों को चुनता है जिन्हें भीषण हत्याओं के लिए दोषी ठहराया गया है। अपने वरिष्ठ अधीक्षक की गंभीर आशंकाओं के बावजूद, वह उन्हें एक बंजर क्षेत्र में ले जाता है और उनसे उम्मीद करता है कि वे इसे उपजाऊ बनाएंगे।

उसे बॉल रोलिंग सेट करने में समय लगता है, क्योंकि कैदी स्वतंत्रता के लिए अप्रयुक्त हो गए हैं। धीरे-धीरे लेकिन निश्चित रूप से, वह उनमें मानवता के लक्षण पैदा करता है, जो तेजी से जेल के निरंकुश वातावरण में गायब हो रहे थे, जहां वे सिर्फ एक संख्या तक कम हो गए थे। वास्तव में, पहली रात वे सो नहीं सकते क्योंकि वे भारी जंजीरों में बंधे रहने के अभ्यस्त हो गए हैं। जेलर उन्हें अपने श्रम में शामिल करता है, उनके लिए खाना बनाता है और उनमें से एक बन जाता है।

जैसे ही आत्मा का क्रमिक जागरण होता है, कहानी विश्वसनीय और जीवंत हो जाती है। कभी-कभी कैदी अपने विश्वास पर खरा नहीं उतर पाते हैं और उन्हें लगता है कि उनका प्रयोग सफल नहीं होने वाला है, लेकिन आदिनाथ की आंखों की सच्चाई हमेशा उनके पुरुषों को वापस लौटने के लिए मजबूर करती है। एक तुलना भगवान की सर्वव्यापी उपस्थिति से की जाती है।

वह दृश्य जहाँ कैदियों में से एक की वृद्ध, आधी-अधूरी माँ अपने बेटों के साथ उनसे मिलने आती है, अपनी गरीबी की स्थिति में मार्मिक है। फिर भी, जब माँ जेलर को प्रशंसा के टोकन के रूप में एक साधारण मिठाई देती है, तो मानवीय भावना का लचीलापन गले में एक गांठ पैदा करता है। हालांकि, जब आदिनाथ ने उन्हें सांसारिक व्यवसाय से परिचित कराया, तो उन्हें पता चला कि यह दुनिया है जो अपराधियों को बनाती है। जैसा कि वे पड़ोस की बाजार में अपनी उपज बेचने के लिए जाते हैं, स्थानीय सब्जी ब्रोकर को खतरा महसूस होता है। वह जेलर के आदमियों पर जीत के लिए विली तरीके का इस्तेमाल करता है। और जब कुछ भी काम नहीं करता है, तो वह फसल को नष्ट करने का फैसला करता है, लेकिन मानवतावाद की आग को फैलने से नहीं रोक सकता है।

एक संदेश आधारित फिल्म होने के बावजूद यह कभी भी पोलमैक्स में नहीं खोती है और सिनेमाई रूप से जीवित रहती है। प्रकाश की परस्पर क्रिया मंत्रमुग्ध कर देने वाली होती है। खिलौना-विक्रेता के रूप में संध्या मनोरंजन भागफल में लाती है। कैदियों के साथ उसकी एक-लाइनर और झड़पें माहौल को हल्का रखती हैं।

संगीतकार वसंत देसाई ने प्रेम और करुणा के अपने शाश्वत संदेश के साथ गीतकार भरत व्यास के साथ "ऐ मालिक तेरे बंदे हम" बनाने के लिए हाथ मिलाया। विडंबना यह है कि एक फिल्म में जिसने अपनी आंखों पर ध्यान आकर्षित किया, 57 साल की उम्र में लड़ते हुए शांताराम उस समय गंभीर रूप से घायल हो गए जब उन्होंने चरमोत्कर्ष में बुल फाइट सीक्वेंस के लिए गोली मार दी। सौभाग्य से, उसकी दृष्टि बच गई। बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में फिल्म ने सिल्वर बीयर जीता। वी। शांताराम गोल्डन ग्लोब जीतने वाले पहले भारतीय थे क्योंकि उन्हें वर्ष 1959 में "दो आंखों" के लिए विशेष सैमुअल गोल्डविन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।

बड़े पैमाने पर, हमारे समाज में जेलों का अस्तित्व वैदिक काल से ही एक प्राचीन घटना है, जहाँ शासकों द्वारा अपराध के खिलाफ समाज

की रक्षा के लिए असामाजिक तत्वों को एक जगह पर रखा गया था। जेलों को एक ' बंदी का घर '[3] के रूप में माना जाता था जहाँ कैदियों को प्रतिशोधी और निवारक दंड के लिए रखा जाता था। सत्रहवीं शताब्दी के अंग्रेजी राजनीतिक सिद्धांतकार जॉन लॉक ने कहा कि पुरुष मूल रूप से अच्छे थे, लेकिन 'समाज में कुछ हताश पुरुषों' को बनाए रखने के लिए कानूनों की जरूरत थी। अपने आपराधिक कानून में व्यक्त समाज का उद्देश्य व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपने स्वयं के अस्तित्व की रक्षा करना है और सभी नागरिकों के लिए एक अच्छा जीवन जीने के लिए, दूसरों के साथ छेड़छाड़ से मुक्त करना संभव बनाना है।कानून लागू करने वाली संस्था को समाज द्वारा अपने नागरिकों की स्वतंत्रता का पर्दाफाश करने के लिए उन्हें उनके कर्तव्यनिष्ठ आचरण के संबंध में हिरासत में लेने की शक्तियां दी गई हैं। 1700 के दशक से पहले[4], सरकारों ने शायद ही कभी अपराधियों को दंड के लिए कैद किया हो। इसके बजाय, लोगों को मुकदमे या दंड का इंतजार करते हुए कैद कर लिया गया। उस समय के सामान्य दंडों में दाहांकन, जुर्माना लगाना, कोड़े मारना और मृत्युदंड (निष्पादन) शामिल थे। अधिकारियों ने अन्य लोगों को कानून तोड़ने से हतोत्साहित करने के लिए सार्वजनिक रूप से अधिकांश अपराधियों को दंडित किया। कुछ अपराधियों को गैलिस नामक जहाजों पर ओआर को पंक्तिबद्ध करने के लिए दंडित किया गया था।

हालांकि, अंग्रेजी और फ्रांसी शासकों ने अपने राजनीतिक दुश्मनों को ऐसी जेलों में रखा जैसे कि टॉवर ऑफ लंदन और पेरिस में बैस्टिल। इसके अलावा, जिन लोगों का पैसा बकाया था और भुगतान में चूक हुई थी, उन्हें देनदार जेलों में रखा गया था। ऐसे कई मामलों में, अपराधियों के परिवार उनके साथ रह सकते हैं और वे प्रसन्न होकर आ सकते हैं।[5] लेकिन कर्जदारों को तब तक जेल में रहना पड़ा जब तक कि उनके कर्ज का निपटारा नहीं हो गया। 1700 के दशक के दौरान, ब्रिटिश न्यायाधीश सर विलियम ब्लैकस्टोन सहित कई लोग फांसी और अन्य कठोर दंडों के उपयोग की आलोचना की। नतीजतन, सरकारें दंड के रूप में अधिक से अधिक कारावास में बदल गईं। शुरुआती जेल अंधेरे, गंदी और भीड़भाड़ वाली थीं। उन्होंने पुरुषों, महिलाओं, बच्चों, खतरनाक अपराधियों, देनदार और पागल सहित सभी प्रकार के कैदियों को एक साथ बंद कर दिया। 1700 के अंत में, ब्रिटिश सुधारक जॉन हॉवर्ड ने जेल की स्थितियों का निरीक्षण करने के लिए यूरोप का दौरा किया। उनकी पुस्तक द स्टेट ऑफ द जेल्स इन इंग्लैंड एंड वेल्स (1777) ने एक ऐसे कानून के पारित होने को प्रभावित किया[6], जिसके परिणामस्वरूप सुधार के लिए आंशिक रूप से डिजाइन की गई पहली ब्रिटिश जेलों का निर्माण हुआ। इन जेलों ने अपने कैदियों को शिथिल महसूस करने का प्रयास किया (गलत काम करने के लिए खेद है) और उन्हें कैदियों के रूप में जाना जाता है। 1787 में, प्रभावशाली फिलाडेलफियंस का एक समूह, ज्यादातर क्वेकर,सार्वजनिक जेलों (अब पेंसिल्वेनिया प्रिज़न सोसाइटी) की गलतियों को दूर करने के लिए फिलाडेल्फिया सोसाइटी का गठन किया[7]। उनका मानना था कि कड़ी मेहनत और ध्यान के माध्यम से कुछ अपराधियों को सुधारा जा सकता है। द क्वैकर्स ने आग्रह किया कि खतरनाक अपराधियों को अहिंसक अपराधियों से अलग रखा जाए और पुरुषों और महिला कैदियों को अलग रखा जाए। इन विचारों को पेंसिल्वेनिया प्रणाली के रूप में जाना जाता है, और 1790 में फिलाडेल्फिया के वॉलनट स्ट्रीट जेल में प्रचलन में लाया गया। इस जेल को संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली जेल माना जाता है[8]I पेंसिल्वेनिया सिस्टम अपराधियों के वर्गीकरण और उनके अपराधों के आधार पर उन्हें अलग करने का पहला प्रयास था। नतीजतन, सबसे खतरनाक कैदियों ने अपना सारा समय अपनी कोशिकाओं में अकेले बिताया। समय में, हालांकि, प्रणाली विफल रही, मुख्यतः क्योंकि भीड़भाड़ ने इस तरह के अलगाव को असंभव बना दिया।

अठारहवीं शताब्दी के दौरान, न्यूयॉर्क जेल अधिकारियों ने जेल संगठन के दो प्रमुख सिस्टम विकसित किए- ऑबर्न सिस्टम और एल्मिरा सिस्टम। 1821 में ऑबर्न (एनवाई) जेल में शुरू की गई ऑबर्न प्रणाली को व्यापक रूप से अपनाया गया[9]। इस प्रणाली के तहत, कैदी रात में एकांत कारावास में रहे और दिन में एक साथ काम किया। सिस्टम ने चुप्पी पर जोर दिया। कैदी बोल नहीं सकते थे, या एक-दूसरे को देख भी नहीं सकते थे। जेल अधिकारियों ने उम्मीद जताई कि इस चुप्पी और अलगाव से कैदियों को अपने अपराधों और सुधार के बारे में सोचना पड़ेगा। उनका मानना था कि सुधार से पहले कैदियों की भावना को तोड़ना होगा।

हालांकि, प्रणाली आंशिक रूप से विफल रही क्योंकि कठोर नियमों और अलगाव ने कैदियों को पागल कर दिया। भारत में समकालीन जेल प्रशासन ब्रिटिश शासन की विरासत है। लॉर्ड मैकाले ने पहली बार 21 दिसंबर, 1835 को भारत में विधान परिषद के लिए एक नोट प्रस्तुत करते हुए[9], भारतीय जेलों में प्रचलित भयानक अमानवीय

स्थितियों को इंगित किया और उन्होंने इसे मानवता के लिए एक चौंकाने वाला करार दिया। उन्होंने सिफारिश की कि जेलों में अनुशासन में सुधार के उपाय सुझाने के लिए एक समिति नियुक्त की जाए। नतीजतन, 2 जनवरी 1836 को, इस उद्देश्य के लिए लॉर्ड विलियम बैंटिक द्वारा एक जेल अनुशासन समिति का गठन किया गया था। समिति ने 1838 में लॉर्ड ऑकलैंड को अपनी रिपोर्ट सौंपी[10]।

तत्कालीन गवर्नर जनरल ने अधीनस्थ प्रतिष्ठानों में व्याप्त भ्रष्टाचार की व्यापकता, अनुशासन में शिथिलता और सार्वजनिक सड़कों पर विलुप्त श्रम पर कैदियों को रोजगार देने की प्रणाली का खुलासा किया। समिति ने कैदियों के अधिक कठोर उपचार की सिफारिश की और नैतिक और धार्मिक शिक्षण, शिक्षा या अच्छे आचरण के लिए पुरस्कार की किसी भी प्रणाली के माध्यम से जेल में बंद अपराधियों के सुधार की सभी धारणाओं को खारिज कर दिया। सर जॉन लॉरेंस, एक प्रसिद्ध न्यायविद्, ने 1864 में फिर से भारतीय जेलों की स्थितियों की जांच की। इसके बाद जेल प्रबंधन और अनुशासन पर गौर करने के लिए दूसरी जांच आयोग लॉर्ड डलहौजी द्वारा नियुक्त किया गया था। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कैदियों के सुधार और कल्याण की अवधारणा पर ध्यान नहीं दिया[11]। इसके बजाय, जेल अनुशासन के नाम पर शारीरिक यातना के साथ पेश जेल रेजिमेंटेशन की एक प्रणाली रखी गई। हालांकि, आयोग ने कैदियों के आवास, आहार, कपड़े, बिस्तर, चिकित्सा देखभाल के संबंध में कुछ विशिष्ट सिफारिशें इस हद तक कीं कि ये जेलों और कैदियों के अनुशासन और प्रबंधन के लिए आकस्मिक थे।

1877 में जेल प्रशासन से विस्तार से पूछताछ करने के लिए विशेषज्ञों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। सम्मेलन ने संकल्प लिया कि एक जेल कानून बनाया जाना चाहिए जो व्यवस्था की एकरूपता को सुरक्षित कर सके और ऐसे बुनियादी मुद्दों को दूर किया जाए जिन्हें कार्यकाल तय करने के लिए स्वीकार किया जाना था। वाक्य। इस सम्मेलन में पारित प्रस्ताव के अनुसरण में, प्रिज़न बिल का एक मसौदा वास्तव में तैयार किया गया था[12], लेकिन अंततः प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण स्थगित कर दिया गया था। चौथा जेल आयोग लॉर्ड डफरिन द्वारा 1888 में जेल प्रशासन को पूछताछ के लिए नियुक्त किया गया था। इस आयोग ने दोहराया कि एकल जेल अधिनियम के अधिनियमित किए बिना एकरूपता हासिल नहीं की जा सकती[13]। फिर से, एक समेकित कारागार विधेयक को कुछ कठोर जेल के दंड प्रदान किया गया था जैसे कि बंदूक की नोक पर दंड, हाथों और पैरों पर बेड़ियाँ लगाना, दंडात्मक आहार, एकान्त कारावास और कोड़े मारना। इस विधेयक को 25 मार्च, 1893 को भारत सरकार के गृह सचिव द्वारा सभी स्थानीय सरकारों को प्रसारित किया गया था।बाद में इसे काउंसिल में गवर्नर जनरल के सामने पेश किया गया और अंततः 1894 का कारागार अधिनियम अस्तित्व में आया, जो वर्तमान कानून प्रबंधन और जेलों का प्रशासन है। यह आजादी के बाद 58 वर्षों सहित 112 वर्षों से लागू है[14]। इन सभी वर्षों में जेलों के उद्देश्यों, प्रबंधन और प्रशासन के संबंध में बहुत सारी नई सोच के बावजूद इसमें कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आया है।

जेल अधिनियम, 1894 के लागू होने के बाद भी देश में जेल की समस्याओं की समीक्षा की प्रक्रिया जारी रही। अखिल भारतीय जेल समिति (1919-20) की नियुक्ति के साथ इस विषय पर पहला व्यापक अध्ययन शुरू किया गया। यह वास्तव में भारत में जेल सुधारों के इतिहास में एक प्रमुख मील का पत्थर है और इसे उचित रूप से देश में आधुनिक जेल सुधारों के कोने का पत्थर कहा जाता है[15]। जेल प्रशासन के इतिहास में पहली बार, अपराधियों के पुनर्वास और पुनर्वास को जेल प्रशासन के उद्देश्यों में से एक के रूप में पहचाना गया था।

सन्दर्भ:

1) अंबरीश मिश्रा । यियर्ज़ ऑफ आ शांताराम क्लॅसिक; द टाइम्स ऑफ इंडिया। रिट्रीव्ड 2014-09-22

2) डॉ किरण बेदी, आई पी एस,डाइरेक्टर जनरल, ब्रद और चेर्मन ऑफ थे कमिटी प्रिपेर्ड बाइ ब्यूरो ऑफ पोलीस रिसर्च एन्ड डेवेलपमेंट मिनिस्ट्री ऑफ होमे अफेर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया न्यूदेल्ही

3) धीरेन्द्रा मोहन दत्ता ;द मोरल कॉन्सेप्षन ऑफ नेचर इन इंडियन फिलॉसोफी; इंटरनॅशनल जर्नल ऑफ एतिक्स, आइल्वाइ, नो. 2 (जन्वरी, 1936).

4) ऑफ कोर्स, लिमिटेशन्स ऑफ स्पेस दो नोट पर्मिट आ कॉंप्रेहेन्सिव डिस्कशन ऑफ ऑल ऑफ द रेलवेंट सोर्सस. इन वॉट फॉलोस, फॉर एग्ज़ँपल, नो अटेंप्ट विल बे मेड टू इंक्लूड द वेरियस निईती `सातरस आंड पुउरनास तट इंक्लूड इंपॉर्टेंट पॅसेजस ओं द ऑरिजिन्स ऑफ सोसाइटी आंड द स्टेट.

5) इंटर एलिया, .रिग वेदा, जे. 124 & amp; 173;ऑल्सो वाइट यजुर वेदा, इक्स. 22, अतरवा वेदा, ईव. 22. 1-7: ईयी. 3.

6) ऐतरएया ब्राह्मा.ना. ई. 14 आ. ब. कीत (ट्रांस.), ऋग्वेदा ब्राह्मानस, मोतीलाल बनार्सिदास. देल्ही, 1971) प. 117.

7) ऐतरएया ब्राह्मा.ना, वीयी. 12; कीत ऑप. सिट., प. 329 .

8) ऐतरएया ब्राह्मा.ना, वीयी, 16; कीत ऑप. सिट., प. 332 .

9) अगगम. ज. एस्ट्लीन कार्पंटर (एड.) द डीघा निकाया (पब्लिश्ड फॉर द पाली टेक्स्ट सोसाइटी बाइ मेयर्स. लुज़ाक ; कंपनी, ल्ट्ड., लंडन. 1960) वॉल. ईयी, प. 83. सी ऑल्सो त. डब्ल्यू. आंड सी. आ. फ. रिस डेविड्स (ट्रांस.) डाइलॉग्स ऑफ द बुद्धा (लुज़ाक ; को., ल्ट्ड., लंडन, 1965) पार्ट ईयी, प्प. 79-80 आंड न. 3 प. 80.

10) आभास्सरा, कार्पंटर (एड.), डीघा निकाया, वॉल. ईयी, प. 84.
11) सत्ता सत्ता टीवी एवा साख्ह्या.म गकचानति. कार्पंटर (एड.), डीघा निकाया. वॉल. ईयी. प. 85
12) क्फ. कार्पंटर (एड.) डीघा निकाया, वॉल. ईयी, प. 199.
13) कार्पंटर (एड.), डीघा निकाया. वॉल. ई1, प. 93 लेटर. द प्रपोर्षन टेंड्स टू बिकम स्टँडरडाइज़्ड अट वन-सिक्स्त.
14) सी राम शरण शर्मा. आस्पेक्ट्स ऑफ पोलिटिकल आइडियास आंड इन्स्टिट्यूशन्स इन एन्षियेंट इंडिया (मोतीलाल बनार्सिदास, देल्ही, 1968) प.58 फ. फॉर आ डिस्कशन ऑफ द ऑरिजिन ऑफ किंगशिप इन द सोशियल नीड फॉर द प्रोटेक्षन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी. ए.ग. प. 58;सो ग्रेट वाज़ द रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रोटेक्टिंग प्रॉपर्टी तट इट वाज़ इनकंबेंट ओं द किंग टू रिस्टोर टू आ सब्जेक्ट द स्टोलन वेल्त अट अन्य कॉस्ट.
15) कार्पंटर (एड.), डीघा निकाया, प. 93-96.